To Increase the Income of Farmers

316. Shri Amit Sihag, M.L.A.: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state the total average income of farmers of Haryana in 2020 in comparison to 2014 togetherwith the steps taken by the Government to increase the income of farmers in state?

Jai Parkash Dalal, Agriculture and Farmers Welfare Minister, Haryana

Sir,

The Agriculture & Farmers Welfare Department, Haryana does not have authenticated data regarding the average income of Farmers in the State. However, various Schemes/programs are being implemented by the Department to uplift the income of the farmers in the state towards achieving the objective of doubling the income of farmers. The steps taken by the department to increase the income of farmers are: -

1. State Government is procuring 9 crops including Paddy, Wheat, Mustard, Maize, Bajra, Moong, Sunflower, Groundnut and Gram from the State Budget at MSP.
2. ₹6000 per year cash incentive is being given to all the farmers in the state through Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana (PM-KISAN).
3. State declared the Sugarcane price at ₹350/- per quintal, which is highest in the country.
4. State Government launched Mera Pani Meri Virasat Scheme to diversify water guzzling crop (Paddy) into alternative crops like maize, cotton, bajra, pulses, vegetables and fruits during Kharif 2020. The Government of Haryana is providing subsidy of ₹7000 per acre as an incentive to farmers for diversification of paddy by alternate crops.
5. To establish 30 integrated pack houses in clusters approach in the 100 Km periphery of Hisar cargo airport.

6. Haryana has taken lead in formation of FPOs and so far, 486 FPOs have been formed with 76000 nos. of farmers members.
7. Under vertical farming an area of 1127 ha. has been covered under poly houses and 2865 ha. under bamboo staking.
8. State Govt. has passed 100 nos. of projects for an amount of Rs. 280.00 crore for executing interest subvention under Agriculture Infrastructure Fund (AIF).
9. Better marketing opportunities created by introduction of e-NAM in mandis and setting up Kisan fresh outlets.
10. Haryana Government is establishing the India International Horticulture Market at Ganaur, Sonipat district in an area of 545 acre.

किसानों की आमदनी बढ़ाना

316. श्री अमित सिहाग, एम.एल.ए.: क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि वर्ष 2014 की तुलना में 2020 में हरियाणा के किसानों की कुल औसत आमदनी कितनी है तथा राज्य में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं ?

जय प्रकाश दलाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा

महोदय जी,

कृषि और किसान कल्याण विभाग, हरियाणा के पास राज्य में किसानों की औसत आमदनी के बारे में प्रमाणित आंकड़े नहीं है। हालांकि, किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तथा राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न योजनाए/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा उठाए कदमः–

1. राज्य सरकार धान, गेहूं, सरसों, मक्का, बाजरा, मूंग, सूरजमुखी, मूंगफली और चना सहित 9 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य बजट से कर रही है।

2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम–किसान) के तहत राज्य के सभी किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये नकद राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जा रही है।

3. राज्य ने गन्ने का मूल्य 350 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया, जो देश में सबसे अधिक है।

4. राज्य सरकार ने खरीफ 2020 में मेरा पानी–मेरी विरासत योजना शुरू की जिसके तहत पानी की अधिक खपत वाली फसल (धान) को वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, सब्जियां और फलों में विविधिकरण किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा धान को वैकल्पिक फसलों में विविधीकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 7000/– रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी प्रदान कर रही है।

5. हिसार कार्गो हवाई अड्डे की 100 कि0 मी0 के परिधि क्षेत्र में 30 इन्टिग्रेटिड पैक हाउस की स्थापित किए जाने की योजना है।

6. हरियाणा ने एफ0 पी0 ओ0 के गठन का बीड़ा उठाया है और अब तक 76,000 किसान सदस्यों के साथ 486 एफ0 पी0 ओ0 का गठन किया गया है।

7. वर्टिक्ल फार्मिंग के तहत 1127 हेक्टेयर क्षेत्र पॉली हाउस और 2865 हेक्टेयर क्षेत्र बैम्बू स्टैकिंग में कवर किया गया है।

8. राज्य सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष (ए0 आई0 एफ0) के तहत ब्याज अधीनता को निष्पादित करने के लिए 280/– करोड़ रूपये की 100 परियोजनाएं पारित की है।

9. मंडियों में ई–नेम लागू करने के साथ–साथ किसान फ्रैश आउटलेट स्थापित करते हुए बेहतर विपणन अवसर पैदा किए गए।

10. हरियाणा सरकार सोनीपत जिले के गनौर में 545 एकड़ क्षेत्र में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट की स्थापना कर रही है।